



"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता" -वेडेले फिलिपा

# दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 25 मार्च 2026 बुधवार

## सम्पादकीय

### युद्ध और ट्रम्प के बदले सुर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट और एनर्जी ठिकानों पर पांच दिनों तक हमला नहीं करने का ऐलान किया है। अगर वह अपनी इस बात पर कायम रहते हैं, तो 28 फरवरी से शुरू हुए मौजूदा युद्ध में यह सबसे सकारात्मक बात होगी। इससे यह छोटी-सी उम्मीद बंधती है कि हेर्मुज स्ट्रेट पर ट्रंप के 48 घंटे वाले अल्टीमेटम के बाद जो युद्ध और तंज होता दिख रहा था, अब शायद उसमें थोड़ा ठहराव आए।

ट्रंप ने दावा किया है कि मीजूदा संकट को लेकर उनकी तैयारी के साथ बातचीत हुई है और यह बेहद सकारात्मक रही। ईरान की तरफ से ऐसी किसी बातचीत का खंडन आया है। हालांकि अगर वार्ता की थोड़ी-सी भी गुंजाइश बनती है, तो सभी पक्षों को उसे दोनों हाथों से थामना चाहिए। इस संकट का केवल एक ही हल है, बातचीत। ट्रंप अगर अपनी तरफ से भी हमलों को कभी लाते हैं, तो वार्ता का रास्ता खुल सकता है। नियामक एशिया के दूसरे देशों को भी इसमें अपनी भूमिका निभानी चाहिए।

दुनिया किस बेताबी से शांति की राह देख रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि भले ही ट्रंप ने पूरी तरह से युद्धविराम नहीं किया, पर क्रूड ऑयल के दाम में 9: की कमी आ गई। उनका पावर प्लांट को निशाना नहीं बनाने का ऐलान, भले वह एकतरफा हो, इस मायने में अहम है कि लड़ाई के इससे तेज होने का खतरा थोड़ा कम हुआ है। अगर ईरान के पावर प्लांट तबाह होते हैं, तो बदले की जवाबी कार्रवाई से होने वाला नुकसान भयानक होगा।

अमेरिका-इराहल और ईरान जंग ने अप्रत्याशित हालात पैदा कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संसद में स्वीकार किया कि देश के सामने बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि हमने कोराना के कठ ऐसी चुनौती का सामना किया है, हमें उसी तरह तैयार रहना है। यह स्वीकारोक्ति अच्छी बात है। किसी भी संकट से निपटने का पहला पड़ाव उसे स्वीकार करना होता है। अब देश किस तरह से इस चुनौती का सामना कर सकता है, सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए। हेर्मुज से होने वाले व्यापार, वहां से आने वाले फर्टिलाइजर्स, खाड़ी में मौजूद भारतीयों और उनके रैमिटेस - सभी को लेकर चिंता है। पीएम ने अपने भाषण में इन सभी को संबोधित किया। ऊर्जा जरूरतों की आपूर्ति में डायवर्सिफिकेशन और घरेलू उत्पादन व स्ट्रेटिजिक रिजर्व को बढ़ाने जैसे कदम अहम हैं। यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि युद्ध की दिशा क्या होगी।

### खतरों में वन्य जीवों की जान

वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए देश भर में चिड़ियाघर और अभयारण्य बनाए गए हैं। मगर संरक्षित स्थलों पर भी सुरक्षा के पर्याप्त बंदोबस्त का अभाव कुछ वन्यजीवों की जान पर भारी पड़ रहा है। हाल ही में उत्तीसगढ़ के सतपुड़ा जिले में एक पशु बचाव केंद्र में आठवारा कुत्तों के हमले में पंद्रह हिरणों की मौत की घटना ने वन्यजीवों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हैरत की बात है कि हिरणों को शिकार से बचाने के लिए जिस सुरक्षित स्थल पर रखा गया है, वहां आठवारा कुत्तों ने ही सेंच लगाकर हमला कर दिया। कहा जा रहा है कि कुत्तों का झुंड बाड़े को तोड़कर अंदर घुस गया। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वहां सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति कैसी होगी। दूसरे, इस घटना में संबधित पशु बचाव केंद्र में तैनात कर्मियों की लापरवाही को भी उजागर किया है। सवाल है कि आठवारा कुत्ते बाड़े को तोड़कर एक के बाद एक हिरण पर हमला करते रहे, तो वहां निगरानी का जिम्मा संभाले वनकर्मियों को इसकी भनक क्यों नहीं लग पाई।

यह बात छिपी नहीं है कि विभिन्न राज्यों में कई जगह चिड़ियाघर और वन्यजीव संरक्षण केंद्रों तो स्थापित कर दिए गए हैं, लेकिन वहां न तो पर्याप्त कर्मियों की तैनाती की गई है और न ही पुख्ता सुरक्षा उपाय किए गए हैं। बाड़ों के बाहर निगरानी के लिए सीसीटीवी और अन्य तकनीकी प्रबंधों का भी अभाव देखा जाता है। जंगली जानवरों के बाड़े से बाहर निकलकर खुले जंगल में गायब हो जाने की खबरें भी अक्सर आती रहती हैं। इससे स्पष्ट है कि बाड़ों की सुरक्षा की नियमित निगरानी नहीं हो पाती है।

छत्तीसगढ़ की घटना भी इसी व्यवस्थागत खामी और लापरवाही की वजह से हुई है। वन विभाग ने संबधित डिट्टी रेंजर और तीन वन श्रवकों को निलंबित कर दिया है, लेकिन क्या यह कार्रवाई काफी है? अक्सर यह देखा जाता है कि इस तरह की लापरवाही में निगले कर्मियों पर निगलन की कार्रवाई करके मामले को रफा-दफा कर दिया जाता है। ऐसे मामलों में जब तक उच्च अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं की जाएगी, तब तक व्यवस्था में सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती।

# इंटरनेट सेवाओं पर संकट के बादल

-डा. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा-

इंटरनेट की दुनिया अभी छह दशक भी पूरे नहीं कर पाई है कि बड़ी संख्या में सामने आ गई है। इसमें कोई दो राय नहीं कि 1960 में जब जैसीआर लिक्वलाइडर ने वैश्विक नेटवर्क की कल्पना की थी उस समय यह सोचा भी नहीं होगा कि तीन से चार दशक में ही इंटरनेट संसार जगत में बड़ी क्रांति लाने में सफल हो जाएगा। अमेरिका-इजरायल व ईरान युद्ध के चलते अभी विश्व के देश ऊर्जा संकट का समाधान तो निकाल ही नहीं पा रहे कि डिजिटल सेवाओं के बाधित होने के मय से दुनिया के देशों की सरकारों की जान संकट में आने लगी है। इंटरनेट आज प्रमुख आवश्यकोंओं में से एक हो गया है। एयर लाइंस, बैंकिंग सेवाएं, संवाद व्यवस्था जिसमें संवाद कायम करने से लेकर सभी तरह की डिजिटल सेवाएं, स्टॉक मार्केट आदि आदि बुरी तरह से प्रभावित होने की संभावनाओं से नकारा नहीं जा सकता। आज इंटरनेट पर निर्भरा बहुत अधिक हो गई है। अमेरिका-ईरान युद्ध को जिस तरह से शुरूआती दौर में ट्रंप द्वारा हलकें में लिया जा रहा था वास्तव यह ट्रंप की गलत कदमी ही रही। वैसे भी रुस क्रेमलिन के युद्ध से ही अमेरिका को संकट लेना चाहिए था। दोनों देश पास पास होने और संसामनों की दृष्टि से रुस अधिक ताकतवर



होने के बावजूद आज तक कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा। अमेरिका ईरान युद्ध के साइड इफेक्ट के रूप में अभी तो उर्जा संकट है पर जिस तरह के हालात बन रहे हैं उन्हें अपने नाले समय में मध्य पूर्व के देशों में पैजल और दुनिया के देशों में लिए इंटरनेट सेवाओं के प्रभावित होने की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। दरअसल जिस तरह से कच्चे तेल और एएसपीजी आदि की दुनिया के देशों में सत्याई हेर्मुज जलमरुम्व के रास्ते होने और ईरान द्वारा इस रास्ते में अरोध बनने से उर्जा संकट गंभीर रूप लेता जा रहा है। ठीक यही समस्या इंटरनेट को लेकर हो सकती है। कारण साफ है, ट्रंप समाप्ति या यों कहे कि सीज फायर के आसार अभी तक बनने नहीं लग रहे तो दूसरी ओर ज्यों ज्यों एक दूसरे को नुकसान

पहुंचाने के अधिक प्रयास होंगे तो ईरान हथियार के रूप में समुद्र में बिछी केबल को भी नुकसान पहुंचाने में कोई गुरेज नहीं करेगा। दुनिया के इंटरनेट ट्रैफिक का प्रमुख रास्ता भी यही है। एक मोटे अनुमान के अनुसार 20 प्रतिशत ट्रैफिक हेर्मुज और लालसागर के रास्ते से गुजरता है। हेर्मुज जलमरुम्व तो हालात यहां तक है कि सकरे स्थान पर तो मात्र 200 फीट की गहराई पर ही सबमरिन केबल लाइनें बिछी हुई हैं। लाम्बा गहरी हालात लालसागर के हैं। वहां भी इंटरनेट सेवाओं के लिए सबमरिन केबल बिछी हुई है। ऐसा कदापि लगाया जा रहा है कि ईरान द्वारा हेर्मुज जलमरुम्व में सुरुंग बिछाने का काम किया जा रहा है और इससे अन्य नुकसान होने के साथ ही फाइबर केबल के भी क्षतिग्रस्त होने की संभावनाओं से

इंकार नहीं किया जा सकता। अरि काश प्रमुख सेवा प्रदाताओं ने इसी क्षेत्र में डेटा सेंटर स्थापित कर रहे हैं। जानकारों के अनुसार हेर्मुज क्षेत्र से करीब 20 और लालसागर क्षेत्र से 17 केबल गुजरती हैं। 2024 में भी लाल सागर क्षेत्र में हूती हमलों के दौरान केबल प्रभावित हो चुकी है। वर्तमान हालातों में यदि सबमरिन केबल प्रभावित भी होती है तो हालात जिस तरह के हैं उनमें प्रभावित केबल को ठीक करने में महीनों ही क्या सात भी लग सकता है और ऐसे में दुनिया के देश एक नए संकट के दौर से गुजरने को मजबूर हो जाएंगे।

इंटरनेट की कल्पना की थी उस समय यह सोचा भी नहीं होगा कि तीन से चार दशक में ही इंटरनेट संसार जगत में बड़ी क्रांति लाने में सफल हो जाएगा। 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क के लिए विट सर्फ और बॉब काह ने टीसीपीआईपी प्रोटोकाल विकसित किया। इंटरनेट की दुनिया में आमूलचूल बदलाव तो टिम बर्नर्स ली द्वारा इन्टरनेटवर्ल्ड वॉल्ड वाइड वेब विकसित किया तो इससे संसार दुनिया ही बदल गई। भारत में सही तौर पर तो 1995 में वीएसएनएल ने इंटरनेट सेवाओं का विस्तार किया। आज बड़ी संख्या में ही कि अमेज, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट आदि के विशाल डेटा सेंटर यूरॉप और सउदी आदि देशों में हैं। यही कारण है कि समुद्री रास्ते से फाइबर केबल भी हेर्मुज जलमरुम्व व लालसागर होते हुए ही हैं। यदि केबल में व्यवधान होती है या किसी तरह से जाने अज्ञाने नुकसान पहुंचता है तो बीडोई काल, इमैनें आदि से लेकर इंटरनेट से जुड़ी सभी तरह की सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं और इसीको लेकर चिंता की लकीरें खिंचने लगी हैं।

वैसे आज संयुक्त राष्ट्र संघ तो बेमानी हो गया है। दुनिया के देशों के अलग अलग बने संगठन बांधे नाटो हो या ब्रिक्स या पिछले कुछ सालों के देश-दुनिया के हालातों में

## बीजेपी ने चुन लिया नया योगी

-अभिनव आकार-

संघाती का मगवा वरन्, हिंदू अस्मिता की बातें, मुस्लिम लुट्टीकरण के खिलाफ सीधी आवाज और राजनीति में कदम रखकर हिंदुओं की रक्षा का वादा। जब हम भारतीय राजनीति में मगवा और सत्ता के मिलन की बातें करते हैं तो सबसे पहला नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आता है। कारण सीधा सा है कि एक संघाती और मठ के प्रमुख से लेकर देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री तक का सफर तक के भारतीय राजनीति में हिंदुत्व की एक नई परिभाषा लिखी। अब ठीक वैसे ही प्रयोग माजपा पश्चिम बंगाल के चुनावी समर में कर रही है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा नाम उभर रहा है जो योगी आदित्यनाथ की याद दिलाता है। ये नाम उत्पल महााराज का है। मूल नाम स्वामी ज्योतिर्मान्यदा। वह भारत के सेवा आश्रम संघ के प्रमुख चेहरे रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने संघ से निकालसित होने के बाद मजपा के टिकट स्वीकार कर ली है और वह उत्तर दिनाजपुर जिले की कलियायान सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यह कोई छोटा फैंसला नहीं है। भाजपा ने जानबूझकर इस चेहरे को चुनाव है।



उत्पल महााराज को टिकट देने का मुख्य कारण उनकी हिंदुवादी छवि और संगठनात्मक अनुभव हैं। वे भारत सेवाश्रम संघ के माध्यम से लंबे समय से लोगों की सेवा कर रहे थे। जिससे उनके स्थानीय स्तर पर जबरदस्त पकड़ है। भाजपा को उनकी मदद है कि उत्पल महााराज के आने से न केवल कलियायान बल्कि आसपास की सीटों पर भी हिंदू मुद्दावादी का भी भाजपा की ओर झुकाव होगा। अब जब भाजपा ने एक हिंदुवादी नेता को टिकट दे ही दिया है तो सवाल उभरना लाजमी है कि क्या उत्पल महााराज बंगाल में पार्टी की हिंदुत्ववादी छवि के प्रमुख नेता बन सकते हैं? जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ माने जाते हैं। तो इस सवाल का जवाब उत्पल महााराज के बयानों और भाजपा की राजनीति में मिलता है। जिस तरह से वे मत्ता बनजी सरकार पर हिंदुओं को हाशिए पर धकेलने का आरोप लगाते हैं उससे साफ है कि भाजपा उन्हें बंगाल में अपने सबसे बड़े हिंदुवादी चेहरे में से एक के रूप में पेश करना चाहती है।

हालांकि, बीते दिनों जारी एक आंतरिक पत्र में संघ ने राजनीति में उनके के कारण उन्हें संघ से निकालसित करने की घोषणा की। उत्पल महााराज का दावा है कि इनका उद्देश्य हिंदुओं को एकजुट बनाना है। हिंदुओं की सेवा करते हुए मैंने महसूस किया कि राजनीति के कारण यह समुदाय

## ब्रिक्स का विस्तार और भारत



-नीरज कुमार दुबे-

ब्रिक्स के विस्तार ने वैश्विक शक्ति संतुलन की बिसात पर एक दांव बजा है, जिसने पश्चिमी प्रमुख को खुली चुनौती दे दी है। भारत के लिए यह उभरती विश्व व्यवस्था में अपनी निर्णायक भूमिका दर्ज कराने का सुनहरा अवसर बन चुका है। आज जब दुनिया बहुवैध व्यवस्था की ओर तेजी से बढ़ रही है, तब ब्रिक्स का विस्तार भारत की सामरिक ताकत को कई गुना बढ़ाने वाला कारक बनकर सामने आया है।

पहले ब्रिक्स पांच देशों का समूह था, जिसकी कुल वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी लगभग 31 प्रतिशत के अनुपात थी। लेकिन विस्तार के बाद इसमें एक सदस्य जुड़ने से यह आंकड़ा लगभग 37 से 40 प्रतिशत तक पहुंच गया है। जिनसंघ के विस्तार से भी यह समूह अब दुनिया की लगभग 45 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। इसका सीधा अर्थ है कि भारत अपने ऐम का प्रमुख स्तर है जो आर्थिक, जनसंख्या और संसामनों के मामले में पश्चिमी देशों को बराबरी की टक्कर दे सकता है।

भारत के लिए सबसे बड़ा सामरिक लाभ यह है कि ब्रिक्स के जरिए वह डॉलर आधारित वैश्विक वित्तीय प्रणाली से विकल्प को मजबूत करने में भूमिका निभा सकता है। न्यू डेवलपिंग बैंक जैसी संस्थाएं पहले ही पश्चिमी वित्तीय संस्थानों के एकांकिकार को चुनौती दे रही हैं। यदि स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा मिलता है, तो भारत को विदेशी मुद्रा दबाव से राहत मिलेगी और उसकी आर्थिक समृद्धता मजबूत होगी।

सामरिक स्तर पर ही वह विस्तार भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। पश्चिम एशिया और अफ्रीका के कई नए सदस्य जुड़ने से भारत की पहुंच उर्जा संसामनों, समुद्री मार्गों और रणनीतिक क्षेत्रों तक बढ़ेगी। यह वही क्षेत्र हैं जहां अब तक चीन अपनी पकड़ मजबूत करता रहा है।

भारत के विस्तार का लिए एक रणनीतिक कदम है, लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी कम नहीं हैं। यदि भारत इन चुनौतियों को संतुलित करते हुए इस काम को प्रामाणी उपायों के साथ ही करता है, तो वह न केवल अपनी वैश्विक ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है बल्कि एक विश्व व्यवस्था के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभा सकता है। यह समय भारत के लिए सिर्फ भागीदारी का नहीं, बल्कि नेतृत्व का है।

वैश्विक हालात दिन प्रतिदिन बद से बदतर हो जा रहे हैं। ऐसे में संसार यह उताव है कि कोई ना कोई ऐसी नियामक संस्था या कोई ना कोई इस तरह की बह्यक्षेत्री व्यवस्था अदृश्य होनी चाहिए जिससे दुनिया के देशों और उनके नागरिकों से जुड़ी सुविधाओं से छेड़छाड़ ना हो इस तरह की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है। किसी भी देश या संगठन को इस तरह की सार्वभौमिक सेवाओं को बाधित करने से रोकने की व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए। क्योंकि दुनिया के देशों में कौन कब सशस्त्रिफि नाता अपने अहम कर्तव्य के लिए दुनिया को संकट में डाल दे इसकी संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। आज उर्जा, पानी, स्वास्थ्य, डिजिटल दुनिया आदि आदि ऐसी सेवाएं हैं जिन्हें प्रभावित होने का खतरा है और यह दुनिया के देशों पर पड़ता है और यह दुःप्रभाव केवल देशों तक ही नहीं अपितु बड़े निवास करने वाले करोड़ों नागरिकों पर सीधे सीधे पड़ता है। ऐसे में पूरी वैश्विक व्यवस्था को ही टपक करने वाले प्रयासों पर कड़क या कारगर कदम लगाना जाना जरूरी हो जाता है। दो देशों के टक्काव के चलते समूची दुनिया या दुनिया के अधिकांश देशों को संकट में नहीं डाला जा सकता। दुनिया के देशों को इस दिशा में दोस पहल करनी ही होगी।

भारत के विस्तार का लिए एक रणनीतिक कदम है, लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी कम नहीं हैं। यदि भारत इन चुनौतियों को संतुलित करते हुए इस काम को प्रामाणी उपायों के साथ ही करता है, तो वह न केवल अपनी वैश्विक ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है बल्कि एक विश्व व्यवस्था के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभा सकता है। यह समय भारत के लिए सिर्फ भागीदारी का नहीं, बल्कि नेतृत्व का है।

भारत के विस्तार का लिए एक रणनीतिक कदम है, लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी कम नहीं हैं। यदि भारत इन चुनौतियों को संतुलित करते हुए इस काम को प्रामाणी उपायों के साथ ही करता है, तो वह न केवल अपनी वैश्विक ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है बल्कि एक विश्व व्यवस्था के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभा सकता है। यह समय भारत के लिए सिर्फ भागीदारी का नहीं, बल्कि नेतृत्व का है।

भारत के विस्तार का लिए एक रणनीतिक कदम है, लेकिन इसके साथ चुनौतियां भी कम नहीं हैं। यदि भारत इन चुनौतियों को संतुलित करते हुए इस काम को प्रामाणी उपायों के साथ ही करता है, तो वह न केवल अपनी वैश्विक ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है बल्कि एक विश्व व्यवस्था के निर्माण में केंद्रीय भूमिका निभा सकता है। यह समय भारत के लिए सिर्फ भागीदारी का नहीं, बल्कि नेतृत्व का है।



